Daily News

डेली न्यूज़

प्रासंगिक

डॉ. लक्ष्मण शर्मा

कोरोना काल में कुपोषण का साया

यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के कारण पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण में वृद्धि होने के कारण निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में अगले 6 माह में 12 लाख बच्चों की मौत हो सकती है। भारत में मौत का यह आंकड़ा 3 लाख हो सकता है, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।

कोरोना संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई और देखते ही देखते यह संक्रमण विश्व में फैल गया। वर्तमान में इस महामारी का मुकाबला दुनिया के निम्न और मध्यम आय वर्ग के लगभग सभी देश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस भयावह रूप से विश्व में मानवीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इस महामारी का सीधा दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर गंभीर रूप में दिखाई पड़ रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से जर्मनी, इटली, इस्राइल और अमेरिका आदि विकसित राष्ट्रों में लाखों लोग काल के मुंह में समा गए। इस महामारी के दुष्प्रभाव कुपोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य, व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं गर्भवती महिलाओं की पूर्व-पश्चात देखभाल जैसी चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकार की लॉकडाउन की घोषणा से देश के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, लघु मध्यम और बड़े उद्योग-धंधे, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, कार्यालय बंद होने के कारण सुदूर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम गतिविधियां स्थगित हो गए, इसके कारण नियमित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ रहा है।

जान बचाना एक चुनौतीभरा कार्य

देश में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 69 प्रतिशत मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। पांच वर्ष की आयु वाला हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में कुपोषण से प्रभावित है। महामारी के इस समय बच्चों में गंभीर कुपोषण का जोखिम अत्यधिक हो सकता है। कोविड-19 को ध्यान में रखकर मध्यम कुपोषित एवं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार इंटरवेंशन को रिडिजाइन करना चाहिए। मध्यम तीव्र कुपोषित बच्चों को लक्षित पूरक आहार कार्यक्रम के माध्यम से एवं अति तीव्र कुपोषित बच्चे जो चिकित्सकीय जटिलताओं के साथ जोखिम में हैं, उनका उपचार समेकित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से तथा बिना चिकित्सकीय जटिलता वाले अति कुपोषित बच्चों का उपचार सामुदायिक स्तर पर किया जाना चाहिए। गरीबी और कुपोषण में फंसे लाखों बच्चों की जान बचाना एक चुनौतीभरा कार्य है। हमें हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में यह सोचना है कि इस माहमारी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए हमें रणनीति बनाने की जरूरत है। यदि हम इस महामारी के खिलाफ लड़ाई को जीतने या हारने के खिलाफ बेपरवाह रहे तो हम गंभीर कुपोषण, डायरिया, निमोनिया और अन्य संक्रमणों के कारण कई बच्चों की जान गंवा सकते हैं।

अभी से परिलक्षित हो रहे दुष्प्रभाव

इस महामारी के पश्चात होने वाले दुष्प्रभाव समाज के स्वास्थ्य पर अभी से परिलक्षित हो रहे हैं। हाल ही में यूनिसेफ की ओर से प्रकाशित विश्व रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज में कुपोषण जैसी स्वास्थ्य चुनौती पर कोरोना संक्रमण महामारी का दुष्प्रभाव अगले छह माह में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण लाखों बच्चे, जिन्हें मध्याह्न का भोजन पूरक पोषण आहार के रूप में मिलता था, नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह ग्रामीण स्तर पर और कच्ची बस्तियों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य स्थानों पर इन कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए जाने वाले पोषण आहार कार्यक्रमों का विघटन महिलाओं और बच्चों के बीच अल्प पोषण की घटनाओं और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। यूनिसेफ ने मई माह में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है कि नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के कारण पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण में वृद्धि होने के कारण निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में अगले 6 माह में 12 लाख बच्चों की मौत हो सकती है। भारत में मौत का यह आंकड़ा 3 लाख हो सकता है।

सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा

लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से गरीब और सीमांत जनसंख्या के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज देने एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सूखे राशन पैकेट वितरित करने की सलाह दी है। सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के अंतर्गत आईसीडीएस के तहत खाद्य सामग्री, सब्जी और फलों आदि की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने और टेक होम राशन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। ज्यादातर राज्यों में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर टेक होम राशन वितरित कर रहे हैं। लॉकडाउन में खाद्य सामग्री बनाने वाली अनेक इकाइयों के बंद होने तथा एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमाओं पर यातायात प्रतिबंध होने के कारण कई स्थानों पर टेक होम राशन के वितरण में बाधा उत्पन्न हुई है। यहां तक कि सूखा राशन, जहां सीमित या पर्याप्त मात्रा में लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, वहां महिलाओं और बच्चों में सूखे राशन को प्राप्त करने का गंभीर खतरा है, जबकि यह सूखा राशन मूल रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए ही दिया जाना है।

पैदा हो गया है आर्थिक संकट

लॉकडाउन के दौरान कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग-धंधे बंद होने के कारण आर्थिक संकट पैदा हो गया है। देश में मजदूरों का सामूहिक पलायन हो रहा है। लाखों एवं करोड़ों मजदूर अपने कार्यस्थल से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों की महिलाएं एवं बच्चे पहले से ही पूरक पोषण आहार सेवाओं को प्राप्त करने में काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ये मजदूर अब राशन प्राप्त करने के लिए अपने कार्यस्थल वाले शहर में सूखा राशन प्राप्त करने के लिए पंजीकृत हो सकते थे, लेकिन पलायन के पश्चात वे अपने गृह राज्य में जाकर पंजीकृत नहीं हो पाएंगे। संसाधनों की कमी के कारण प्रवासी आबादी को उचित भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक गंभीर चुनौती होगी, जिससे पर्याप्त आहार की कमी के कारण बच्चों और महिलाओं में कुपोषण का खतरा बढ़ जाएगा। लॉकडाउन के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित निगरानी गतिविधियों और सेवाएं देने में संलग्न हैं। इस गंभीर कठिन समय में ये कार्यकर्ता पहले से ही उच्च जोखिम वाली जिम्मेदारी से बोझिल हैं। ऐसी स्थिति में उनसे यह अपेक्षा करना कि पूर्व की भांति वे कार्य करें, यह गलत होगा।